भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
मौखिक प्रश्न संख्या : 144
गुरुवार, 5 दिसंबर, 2024/14 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

नये विमानपत्तनों का विकास

***144. श्री भर्तृहरि महताबः**
श्री पी. पी. चौधरीः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का अगले पांच वर्षों में 50 अतिरिक्त विमानपत्तन विकसित करने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो प्रत्येक विमानपत्तन को पूरा करने के लिए क्या विस्तृत योजना और समय-सीमा तैयार की गई है;

(ख) उक्त पहल से देश भर में विमानपत्तन इको सिस्टम को किस प्रकार बढ़ाए जाने का उद्देश्य है;

(ग) विमानपत्तन नेटवर्क के विस्तार से रोजगार सृजन में किस प्रकार योगदान मिलेगा और विमानन क्षेत्र में व्यावसायिक कार्यकलापों को किस प्रकार बढ़ावा मिलेगा;

(घ) क्या सरकार ने अतिरिक्त विमानपत्तनों के लिए किसी स्थान की पहचान की है और व्यवहार्यता सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो देश भर में, विशेष रूप से कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्रस्तावित विमानपत्तनों के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, विशेष रूप से राजस्थान में, अनुमानतः कितना निवेश आवश्यक है;

(च) क्या सरकार का महाराष्ट्र के पालघर जिले में विमानपत्तन विकसित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार ने हाल ही में राजस्थान में पाली विमानपत्तन, महाराष्ट्र में लातूर विमानपत्तन, मध्य प्रदेश में सिंगरौली और झारखंड में बोकारो विमानपत्तन के संचालन के लिए पहल की है और यदि हां, तो उनमें से प्रत्येक विमानपत्तन का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू)

(क) से (छ) : विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*****

"नये विमानपत्तनों का विकास" के संबंध में श्री भर्तृहरि महताब और श्री पी. पी. चौधरी द्वारा पूछे गए दिनांक 05.12.2024 के लोक सभा मौखिक प्रश्न संख्या 144 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (च): देश में असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों से क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने तथा आम जनता के लिए हवाई यात्रा सस्ती उपलब्ध कराने हेतु नागर विमानन मंत्रालय ने दिनांक 21-10-2016 को क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) – 'उड़ान' (उड़े देश का आम नागरिक) शुरू की है। भारत सरकार (जीओआई) ने 1000 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता से 03 वर्ष की अवधि अर्थात दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2026 तक 50 से अधिक असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों/हेलीपैडों/वाटर एयरोड्रोमों तथा उन्नत लैंडिंग ग्राउंड्स (एएलजी) के पुनरुद्धार/विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस संबंध में विकास के लिए 36 हवाईपट्टियों की पहचान की गई है। आज तक, इस योजना के तहत 87 असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों (13 हेलीपोर्टों और 2 वाटर एयरोड्रोमों सहित) को जोड़ने वाले 613 मार्गों को कार्यशील किया गया है। 2.87 लाख आरसीएस उड़ानों के माध्यम से 146 लाख से अधिक घरेलू यात्रियों ने यात्रा की है।

भारत सरकार ने ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (जीएफए) नीति, 2008 के अनुसार देश भर में 21 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी प्रदान की है, जिनमें गोवा में मोपा, महाराष्ट्र में नवी मुंबई, शिरडी और सिंधुदुर्ग, कर्नाटक में कालाबुरागी, विजयपुरा, हसन और शिवमोग्गा, मध्य प्रदेश में डाबरा (ग्वालियर), उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और नोएडा (जेवर), गुजरात में धोलेरा और राजकोट (हीरासर), पुदुचेरी में कराईकल, आंध्र प्रदेश में दगडार्थी, भोगापुरम और ओरवाकल (कुर्नूल), पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, सिक्किम में पाक्योंग, केरल में कन्नूर और अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर शामिल हैं।

इनमें से 12 ग्रीनफ़ील्ड हवाईअड्डों अर्थात दुर्गापुर, शिरडी, कन्नूर, पाक्योंग, कालाबुरागी, ओरवाकल (कुर्नूल), सिंधुदुर्ग, कुशीनगर, ईटानगर, मोपा, शिवमोग्गा और राजकोट (हीरासर) में हवाईअड्डों को कार्यशील कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने 9 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों अर्थात राजस्थान में अलवर, मध्य प्रदेश में सिंगरौली, हिमाचल प्रदेश में मंडी, केरल में कोट्टयम, ओडिशा में पुरी, असम में डोलू, तमिलनाडु में परंदूर, राजस्थान में कोटा और कर्नाटक में रायचूर में हवाईअड्डों के निर्माण के लिए 'साइट क्लीयरेंस' भी प्रदान कर दिया है। ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (जीएफए) नीति, 2008 के अनुसार, भारत सरकार को महाराष्ट्र के पालघर में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण के लिए महाराष्ट्र सरकार या किसी हवाईअड्डा विकासकर्ता से 'साइट क्लीयरेंस' के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

वित्तपोषण सहित हवाईअड्डा परियोजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और संबंधित राज्य सरकार (यदि राज्य सरकार परियोजना प्रस्तावक है) सहित संबंधित हवाईअड्डा विकासकर्ता की है।

हवाईअड्डे, आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में उभरे हैं और इनका राज्य की अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव होता है। नागर विमानन क्षेत्र और आर्थिक विकास के बीच का संबंध सर्वविदित है। हवाईअड्डों के विकास से यात्रियों की आवाजाही, पर्यटन विकास, रोजगार सृजन और भूमि मूल्यांकन की सर्किल दरों में वृद्धि होती है, जिससे संबंधित राज्य में विभिन्न करों/स्टांप शुल्क, आदि का संग्रह बढ़ता है और देश का समग्र विकास होता है। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) के अध्ययन से पता चलता है कि हवाई संपर्क का आर्थिक गुणक 3.25 और रोजगार गुणक 6.1 होता है।

(छ): पाली जिले में सोजत हवाईपट्टी, सिंगरौली हवाईपट्टी और लातूर हवाईपट्टी, 'उड़ान' दस्तावेज में असेवित हवाईपट्टियों की सूची में उपलब्ध हैं। तथापि, 'उड़ान' के तहत बोली प्रक्रिया के पांच चरणों तक किसी भी एयरलाइन प्रचालक ने वहां आरसीएस उड़ान परिचालित करने का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

'उड़ान' के तहत बोली प्रक्रिया के दूसरे चरण के दौरान विकास और आरसीएस उड़ानों के परिचालन के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के स्वामित्व वाले बोकारो हवाईअड्डा, झारखंड की पहचान की गई है। बोकारो हवाईअड्डे पर विकास कार्य पूरा हो चुका है। हवाईअड्डे के तैयार होने पर, एयरलाइन, पटना और कोलकाता को जोड़ने वाली आरसीएस उड़ानों का परिचालन शुरू कर सकती है।

*****